



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 22, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 680/79-वि-1-2022-1-क-19-2022

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 जिससे पंचायती राज अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) संक्षिप्त नाम और अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन	2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15 में,— (क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे; (ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।
धारा 28 का संशोधन	3-मूल अधिनियम की धारा 28 में,— (क) उपधारा (11) में शब्द "आधे से अधिक" के स्थान पर शब्द "अन्यून दो-तिहाई" रख दिये जायेंगे; (ख) उपधारा (13) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।
निरसन और व्यावृत्ति	4-(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश संख्या 8
सन् 2022

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 15 और 28 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। उक्त धाराओं की उपधारा (11) में यह उपबंध है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है तो यथास्थिति प्रमुख या अध्यक्ष इस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जायेंगे। उक्त धाराओं की उपधारा (13) में यह उपबंध है कि अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, यथास्थिति किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी। इन उपबंधों के कारण क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में सदैव अस्थायित्व की स्थिति बनी रही। क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह उपबंध किया जाय कि यथास्थिति धारा 15 के अधीन किसी प्रमुख के विरुद्ध या धारा 28 के अधीन किसी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, क्रमशः किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के दो वर्षों के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी और क्षेत्र पंचायत प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष तब तक अपना पद धारण करने से प्रविरत नहीं होंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से न लाया जाय।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 680 (2)/LXXIX-V-1-2022-1(ka)-19-2022

Dated Lucknow, December 13, 2022

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2022) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 13, 2022. The Panchayati Raj Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022
(U.P. Act no. 14 of 2022)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :-

- | | |
|--|--|
| 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force with effect from October 4, 2022. | |
| 2. In section 15 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the "principal Act"),- | Amendment of section 15 of U.P. Act no. 33 of 1961 |
| (a) in sub-section (11), <i>for</i> the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be <i>substituted</i> ; | |
| (b) in sub-section (13), <i>for</i> the words "one year", the words "two years" shall be <i>substituted</i> . | |
| 3. In section 28 of the principal Act,- | Amendment of section 28 |
| (a) in sub-section (11), <i>for</i> the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be <i>substituted</i> ; | |
| (b) in sub-section (13), <i>for</i> the words "one year", the words "two years" shall be <i>substituted</i> . | |
| Repeal and saving | |
| 4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 is hereby repealed. | U.P. Ordinance no. 8 of 2022 |

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) has been enacted to provide for the establishment of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats in the State of Uttar Pradesh. Sections 15 and 28 of the said Act, deals with the motion of no-confidence in Pramukh of Kshettra Panchayats and Adhyaksha of Zila Panchayats respectively. Sub-section (11) of the said section provides that if the motion of no-confidence is carried with the support of more than half of the total numbers of elected members of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats, as the case may be, then the Pramukh or Adhyaksha, as the case may be, shall cease to hold office as such. Sub-section (13) of the said sections provides that no notice of motion of no-confidence shall be received within one year of assumption of office by the Pramukh or the Adhyaksha, as the case may be. Due to these provisions there was always a situation of instability in the Kshettra Panchayats and Zila Panchayats. With a view to ensure stability of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats it was decided to amend the said Act to Provide that no notice of motion of no-confidence against a Pramukh under section 15 or against an Adhyaksha under section 28, as the case may be, shall be received within two years of the assumption of office by a Pramukh or an Adhyaksha respectively and the Pramukh of Kshettra Panchayats or Adhyaksha of Zila Panchayats shall not cease to hold office unless no-confidence motion is carried with the support of not less than two-thirds of the total number of elected members thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttar Pradesh Ordinance no. 8 of 2022) was promulgated by the Governor on October 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.